मुक्त चिन्तन
News Letter
उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अधिनियम संख्या 10, 1999 द्वारा स्थापित

मुक्त चिन्तन 05 मई, 2026

मुक्त विश्वविद्यालय में स्नातक रोजगारपरकता पर तीन दिवसीय कार्यशाला

यूपीआरटीओयू-CEMCA कार्यशाला में NEP 2020, PMKVY और गिग इकॉनमी पर जोर

उ.प्र. राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज में मंगलवार दिनांक 05 मई, 2026 को उ0 प्र0 राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज और राष्ट्रमंडल शैक्षिक मीडिया केंद्र एशिया, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में में "स्नातक रोजगारपरकता में वृद्धि" विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला आज दूसरे दिन में प्रवेश कर गई। उक्त कार्यशाला विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्या शाखा के शिक्षक सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

संस्थागत प्रतिबद्धता पर बोलते हुए आयोजन सचिव डॉ. गौरव संकल्प ने बताया कि माननीय कुलपति प्रो. सत्यकाम जी ने सभी विद्या शाखाओं को नए रोजगारपरक और कौशल–आधारित कार्यक्रम विकसित करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। "माननीय कुलपति चाहते हैं कि यूपीआरटीओयू डिग्री देने से आगे बढ़कर कौशल देने वाला विश्वविद्यालय बने। अब हर नए पाठ्यक्रम प्रस्ताव में बाजार का अध्ययन, उद्योग की प्रतिक्रिया और स्पष्ट जॉब रोल शामिल करना होगा। डॉ. संकल्प ने बताया कि विश्वविद्यालय एमबीए, पत्रकारिता और कंप्यूटर एप्लीकेशन कार्यक्रमों की NSQF स्तरों और सेक्टर स्किल काउंसिल मानकों के अनुरूप समीक्षा कर रहा है।

संयोजक डॉ. त्रिविक्रम तिवारी तकनीकी सत्रों का समन्वय करते हुए कहा कि शिक्षक समूह हैंड्स–ऑन अभ्यासों में लगे हैं: नेशनल करियर सर्विस पोर्टल से जॉब रोल की पहचान करना, QP&NOS को पाठ्यक्रम परिणामों से मैप करना और लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, डिजिटल मार्केटिंग व स्वास्थ्य सहायक जैसे क्षेत्रों में 30–घंटे के माइक्रो–क्रेडेंशियल का मसौदा तैयार करना। "विचार यह है कि अलगाव को तोड़ा जाए। आज एक इतिहास के प्रोफेसर ODOP के तहत 'हेरिटेज टूरिज्म और लोकल गाइडिंग' पर मॉड्यूल डिजाइन कर रहे हैं।

कार्यशाला का अपेक्षित परिणाम 15–20 नए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रमों का सेट है जो सीधे बाजार की मांग, NEP 2020 के लक्ष्यों और गिग इकॉनमी की वास्तविकताओं पर आधारित होंगे। पाठ्यक्रमों का मसौदा जून 2026 तक विद्या परिषद के समक्ष रखा जाएगा ताकि जुलाई सत्र से इन्हें शुरू किया जा सके।

भारत को 2030 तक हर साल 90 लाख गैर–कृषि रोजगार सृजित करने की जरूरत है। ऐसे में यूपीआरटीओयू–CEMCA की यह पहल दिखाती है कि कैसे मुक्त विश्वविद्यालय नीति, शिक्षाशास्त्र और प्लेसमेंट को जोड़कर शिक्षा–रोजगार की लगातार बनी खाई को पाट सकते हैं।

कौशल अब शिक्षा के समानांतर नहीं, बल्कि शिक्षा ही है : डॉ. प्रदीप के. चौधरी

संदर्भ रखते हुए कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग सेमका प्रोजेक्ट के सलाहकार डॉ. प्रदीप कुमार चौधरी ने रेखांकित किया कि स्नातक रोजगारपरकता को राष्ट्रीय नीति और बाजार बदलावों के आलोक में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कार्यशाला के उद्देश्यों को सीधे NEP 2020 से जोड़ा, जिसका लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (GER) प्राप्त करना और कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना है। डॉ. चौधरी ने कहा कि लचीली, कौशल–आधारित डिग्रियां देकर इस GER लक्ष्य को पूरा करने में मुक्त विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका है।

उन्होंने चर्चा को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) से भी जोड़ा। 2015 में शुरू होने के बाद से PMKVY के तहत देशभर में 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 1.1 करोड़ से अधिक को PMKVY 4.0 के मांग–आधारित मॉडल के तहत प्रमाणित किया गया है। PMKVY जैसी योजनाएं दिखाती हैं कि कौशल अब शिक्षा के समानांतर नहीं, बल्कि शिक्षा ही है। उत्तर प्रदेश इसका प्रमुख लाभार्थी रहा है, जहां उ.प्र. कौशल विकास मिशन ने 2017 से अब तक 16 लाख से अधिक युवाओं को कुशल बनाया है और 6.5 लाख को रोजगार दिलाया है।

भविष्य के रोजगार बाजारों पर बात करते हुए डॉ. चौधरी ने 'गिग वॉर' के लिए तैयार रहने पर जोर दिया। नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि भारत का गिग कार्यबल 2020–21 में 77 लाख से बढ़कर 2029–30 तक 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। "स्नातकों को केवल नौकरियों के लिए नहीं, बल्कि फ्रीलांसिंग, प्लेटफॉर्म वर्क और सूक्ष्म उद्यमिता के लिए भी प्रशिक्षित करना होगा। पाठ्यक्रमों में डोमेन ज्ञान के साथ डिजिटल, वित्तीय और संचार कौशल भी विकसित करने होंगे। उन्होंने भारत सरकार और उ.प्र. सरकार की प्रमुख पहलों कृ डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मिशन रोजगार और एक जिला एक उत्पाद (ODOP) को भी रेखांकित किया, जिन्हें विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम डिजाइन में शामिल करना चाहिए। ODOP ने अकेले 1.6 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया है और उ.प्र. में 25 लाख कारीगरों को सहारा दिया है।